बिहार विधान-सभा

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग-2 -- कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

वृहस्पतिवार, तिथि 30 जून, 1983।

विषय-सूची

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं :		1—4
शून्य-काल की चर्चाएं :		4—8
(क) महिला थाना की व्यवस्था	...	4
(ख) महन्थ द्वारा पर्चाधारियों पर जुल्म	...	4-5
(ग) जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति	...	5
(घ) पेयजल का भारी संकट	...	5-6
(ङ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा भयंकर लूट	...	6
(च) हरिजन टोली में पानी की व्यवस्था	...	6
(छ) अर्जित जमीन की मुआवजा का भुगतान	...	6-7
(ज) थाना प्रभारी द्वारा आतंक	...	7
(झ) पुल का निर्माण	...	7
(ञ) डॉ० नन्दकुमार मिश्रा का स्थानान्तरण	...	8
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य:	...	8-9
पकड़ीदयाल प्रखंड में नहर का निर्माण	...	8
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :	...	9—11
(अ) मजदूर और भूधारी के बीच संघर्ष	...	9-10

10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 50 घायल हो गये। इसी प्रकार उसके तुरंत बाद ही चन्द्रहाटी (मुजफ्फरपुर) में भी उसी दिन एक निजी बस का ट्रक से सीधी टक्कर हो जाने के कारण 15 व्यक्तियों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी तथा 40 से अधिक व्यक्ति घायल हुए। इस प्रकार निजी बस के चालकों के द्वारा लापरवाही बरतने के कारण लोगों की जान जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा बसों के चलने पर निर्धारित गति तय की गयी है उसे निजी बस वाले उल्लंघन कर तेज गति से बस चलाते हैं जिससे आये दिन इस प्रकार की घटना घट रही है।

पटना से मुजफ्फरपुर जाने वाली निजी बसें स्पीडब्रेकर पर भी अपनी रफ्तार कम नहीं करते। उक्त सड़क पर हाजीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर के बीच किसी स्थान पर भी ट्रफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है, यह भी घट रही अप्रिय घटना का एक मुख्य कारण है।

महात्मा गांधी सेतु चालू हो जाने के बाद इस सड़क पर निजी बसों का चलना बढ़ सा गया है। हर दो तीन मिनट पर निजी बसें उक्त सड़क से होकर गुजरती हैं जो परिवहन विभाग के नियम कानूनों को तोड़कर बसें चलायी जाती हैं जिससे आये दिन लोगों की जान जा रही है।

अतः मैं मांग करता हूं कि आज के सदन के कार्य को स्थगित कर जन सुरक्षा के हित में इस पर बहस चलायी जाय ताकि इस प्रकार की अप्रिय घटना से लोगों को त्राण मिल सके।

शून्य-काल की चर्चाएं :

(क) महिला थाना की व्यवस्था।

श्रीमती तारा गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं फिर भी इन पर जोर जुल्म सीमा पार कर रहा है। मारे शर्म के ये अपना दुःख दर्द कह नहीं पातीं। अतः मैं मांग करती हूं कि महिला थाना का एक प्रावधान किया जाए।

(ख) महन्थ द्वारा पर्चाधारियों पर जुल्म।

श्री राम लषन राम "रमण"—अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड के दाहुर ग्राम निवासी महन्थ द्वारा सरकारी पर्चाधारी, बटाईदारों एवं गरीब मजदूरों पर डकैती का झूठा मुकदमा दायर कर परेशान किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि उक्त

महन्थ की सीमा से अतिरिक्त जमीन पर सरकार ने उक्त गरीबों को पर्चा दिया है जिस पर महन्थ ने जबरन कब्जा कर रखा है तथा विभिन्न मुकदमों द्वारा गरीबों को तबाह कर रहा है।

उपरोक्त झूठे डकैती में फंसाने की बातों को पुलिस अधिकारी के साथ ही आम लोग जानते हैं तथा इसकी भर्त्सना भी करते हैं। खजौली थाना के प्रभारी श्री के० डी० चौधरी के द्वारा झूठा मुकदमा साबित किया गया है पर एक उच्चाधिकारी द्वारा महन्थ से पैसा लेकर मामले को उलटने एवं प्रभारी दारोगा को परेशान करने की साजिश की जा रही है। मधुबनी के एस० पी० से मामले में हस्तक्षेप करने एवं न्याय करने का आग्रह किया गया है। सरकार शीघ्र हस्तक्षेप कर गरीबों को न्याय दिलावे।

(ख) जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति।

श्री घनश्याम महतो—अध्यक्ष महोदय, सिंहभूम जिला में 1983 के मार्च, अप्रैल एवं मई महीना में करीब बारह सौ शिक्षक को सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में बहाली किया है जिसमें करीब तीन सौ शिक्षक का शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र जाली है। रुपये के बल पर जाली प्रमाण-पत्र को सही मानकर शिक्षकों को बहाल किया गया है। दूसरी तरफ सही शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त प्रार्थी रुपये के अभाव में बहाली से वंचित हैं। लोग आश्चर्य चकित होकर देख रहे हैं कि जो लोग कभी स्कूल और कालेजों का मुंह नहीं देखा है वह कैसे शिक्षक पद पर बहाल हो गया है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार 1983 में सिंहभूम जिला में बहाल किए गए सभी शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की विभागीय जांच करा दें और दोषी पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर कड़ी-से-कड़ी सजा दें।

(ग) पेयजल का भारी संकट।

श्री मदन मोहन चौधरी—दरभंगा जिला में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। सुखाड़ के कारण आदमी तथा जानवर दोनों के लिए पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जिला में आधे से ज्यादा नलकूप चोक पड़ा है। गांव-गांव में चापाकल खराब रहने के कारण ग्रामीणों को पेयजल के लिए भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिला में चार सौ से अधिक ऐसे चापाकल हैं जो चोक पड़े हुए तथा उनकी मरम्मत के लिए स्थानीय विभाग को आठ लाख रुपये की जरूरत है जो विभाग